

[2025] 3 एस.सी.आर. 1309 : 2025 आईएनएससी 410

इमरान प्रतापगढ़ी

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(2025 की आपराधिक अपील संख्या 1545)

28 मार्च 2025

[अभय एस. ओका\* और उज्ज्वल भुयान, जे. जे.]

### विचारार्थ मुद्दा

क्या तथ्यों के आधार पर, बी. एन. एस. की धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया है, राज्यसभा के सदस्य अपीलकर्ता के खिलाफ बनते हैं; क्या हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता द्वारा उसके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज करने में गलती की।

### हेड नोट्स

भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 196, 197(1), 299, 302, 57 और 3(5) - अपीलकर्ता, जो राज्यसभा का सदस्य है, ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सामूहिक विवाह समारोह का वीडियो पोस्ट किया था, और वीडियो के बैकग्राउंड में, विवादित कविता के शब्द बोले गए थे - अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि कविता ने अन्य बातों के अलावा सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा दिया - क्या अपराध बनते हैं:

आयोजित: धारा 196 के तहत कोई अपराध तब नहीं बनता जब बोले गए या लिखे गए शब्द, या संकेतों या दिखाई देने वाले चित्रणों से धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, समुदाय या किसी अन्य आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया जाता है - अपराध तब बनेगा जब बोले गए या लिखे गए शब्द, या संकेत या दिखाई देने वाले चित्रण, अलग-अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य या दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं या बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं - इस मामले में, कविता का किसी धर्म, जाति, समुदाय या किसी विशेष

\*लेखक

समूह से कोई लेना-देना नहीं है - कविता के शब्द असामंजस्य या नफरत या दुर्भावना की भावनाएं पैदा नहीं करते या उन्हें बढ़ावा नहीं देते - यह केवल शासक द्वारा किए गए अन्याय को चुनौती देना चाहती है - यह कहना असंभव है कि अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं या भंग करने की संभावना है या राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करते हैं - इसके अलावा, धारा 196 \* BNS के लेखक में मेन्स रिया को पढ़ा जाना है - हालांकि, इस मामले में, बोले गए शब्दों के पाठ और जिस संदर्भ में वे बोले गए थे, उसे देखते हुए, अपीलकर्ता पर कोई मेन्स रिया थोपना असंभव है - अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 196, 197, 299 और 302, BNS के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है - FIR यांत्रिक रूप से दर्ज की गई थी और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है- आक्षेपित आदेश को रद्द किया गया। [पैरा 14,31,34,36,43]

**भारतीय न्याय संहिता, 2023-s. 197- राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोप, दावे:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** जिस कविता की बात हो रही है, वह कोई आरोप नहीं लगाती या प्रकाशित नहीं करती और उसका किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है - यह सुझाव नहीं देती कि किसी भी वर्ग के लोगों को नागरिक के तौर पर उनके अधिकारों से इसलिए वंचित किया गया है क्योंकि वे किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय के सदस्य हैं - यह कोई ऐसा दावा, सलाह, दलील या अपील नहीं करती या प्रकाशित नहीं करती जिससे असामंजस्य या दुश्मनी या नफरत या दुर्भावना की भावना पैदा हो - यह कविता कोई भी गलत या गुमराह करने वाली जानकारी प्रकाशित या प्रसारित नहीं करती।[पैरा 16]

**भारतीय न्याय संहिता, 2023-किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना-चाहे तथ्यों पर हो, अपीलकर्ता का इरादा किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना था:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** अपीलकर्ता का कोई भी काम किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उसके धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के इरादे से नहीं किया गया था - कविता सिर्फ शासकों को यह बताती है कि अगर अधिकारों की लड़ाई में अन्याय हुआ तो क्या प्रतिक्रिया होगी।[पैरा 17]

भारतीय न्याय संहिता, 2023 - धारा 302 - किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुँचाने के इरादे से शब्द बोलना, आदि - धारा 302, यदि वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होती है:

अभिनिर्धारित किया गया: यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर इरादे से कोई शब्द कहे जाएं तो धारा 302 के तहत कोई अपराध नहीं होगा। धारा 302, सीधे तौर पर लागू नहीं होती।[पैरा 18]

भारतीय न्याय संहिता, 2023- धारा 57- जनता द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध को बढ़ावा देना:

अभिनिर्धारित किया गया: यहां तक कि अगर यह माना जाता है कि अपीलकर्ता ने कुछ अपराध किया है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने आम तौर पर जनता द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या या वर्ग द्वारा अपराध करने के लिए उकसाया है।[पैरा 19]

भारत का संविधान - अनुच्छेद 19, 51-A - बोलने की आज़ादी आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा - पुलिस अधिकारियों का संविधान का पालन करने का कर्तव्य - अनुच्छेद 51-A (a) के तहत पुलिस का दायित्व - भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 - धारा 173(1) - संज्ञेय मामलों में जानकारी - धारा 173(3) का उद्देश्य - यदि आरोप अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत कानून द्वारा कवर किए गए अपराध करने का है और यदि धारा 173(3) लागू होती है, तो प्रारंभिक जांच की जाएगी:

अभिनिर्धारित किया गया: पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए - विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के आदर्शों में से एक है - अनुच्छेद 19(1)(a) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है - पुलिस तंत्र अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत राज्य का एक हिस्सा है - पुलिस अधिकारी नागरिक होने के नाते संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं - वे सभी नागरिकों को दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए बाध्य हैं - खंड (2) के तहत आने वाले कानून एक अपवाद के रूप में संरक्षित हैं बशर्ते वे उचित प्रतिबंध लगाते हों - अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचीबद्ध स्वतंत्रता का एक अपवाद है - अनुच्छेद 19(2) में दिए गए उचित प्रतिबंध उचित रहने चाहिए और मनमाने और दमनकारी नहीं होने चाहिए - अनुच्छेद 19(2) को अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकारों, जिसमें

भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती - इसलिए, जब आरोप अनुच्छेद 19 के खंड (2) में संदर्भित कानून द्वारा कवर किए गए अपराध के कमीशन का हो, यदि धारा 173 की उप-धारा (3) लागू होती है, तो यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना हमेशा उचित होता है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं - यह सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार संरक्षित रहें - इसलिए, ऐसे मामलों में, धारा 173 की उप-धारा (3) में संदर्भित उच्च पुलिस अधिकारी को सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देनी चाहिए - इसलिए, जब संज्ञेय अपराधों के कमीशन का आरोप लगाया जाता है, जहां सजा 7 साल तक की कैद है, जो बोले गए या लिखे गए शब्दों पर आधारित है, तो धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत विकल्प का प्रयोग करना और यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना हमेशा उचित होगा कि आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं - यदि ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा उप-धारा (3) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है जिसने अनुच्छेद 19 (1)(a) के तहत अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है, भले ही अनुच्छेद 19 का खंड (2) लागू न हो - यदि, ऐसे मामलों में, धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, [पैरा 29,30]

**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023-s.173 (3)- संज्ञेय मामलों में जानकारी-  
भारतीय न्याय संहिता, 2023-s. 196, 197 (1), 299, 302, 57 और 3 (5)-  
चाहे तथ्यों पर, बी. एन. एस. एस. की खंड 173 की उप-खंड (1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य था:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** धारा 173 की उप-धारा (3) संज्ञेय अपराध होने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले अधिकारी को यह तय करने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार देती है कि क्या आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है - यह विकल्प तब उपलब्ध होता है जब कथित अपराध 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा के लायक हो - मौजूदा मामले में, धारा 57 को छोड़कर सभी अपराधों में 7 साल से कम की कैद की सजा है - धारा 57, देखने में, लागू नहीं होती है - इसलिए, यह विकल्प मौजूदा मामले में पुलिस अधिकारी के पास भी उपलब्ध था लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया - मामले के तथ्यों के अनुसार, धारा 173 की उप-धारा (3) का सहारा लिए बिना

भी, पुलिस अधिकारी को दी गई जानकारी धारा 196, 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित नहीं करती थी। [पैरा 28, 31]

**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023-s.173 (1)- संज्ञेय मामलों में जानकारी-  
भारतीय न्याय संहिता, 2023-ss. 196, 197 (1), 299,302,57 और 3 (5):**

**अभिनिर्धारित किया गया:** पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को दी गई जानकारी में लगाए गए आरोपों की जांच ऑफिसर को सिर्फ यह पता लगाने के लिए करनी चाहिए कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है - जानकारी को सही मानते हुए, ऑफिसर को यह तय करना होगा कि क्या यह संज्ञेय अपराध करने का मामला बनता है - अगर आरोप संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, तो जब तक अपराध धारा 173 की उप-धारा (3) में नहीं आता, FIR दर्ज करना अनिवार्य है - धारा 196, BNS के तहत दंडनीय अपराध के मामले में यह तय करने के लिए कि क्या बोले गए या लिखे गए शब्द, या संकेत या दृश्य प्रस्तुतियों या इलेक्ट्रॉनिक संचार या किसी अन्य तरीके से, धारा में बताए गए परिणाम होते हैं, जिस पुलिस ऑफिसर को जानकारी दी गई है, उसे लिखे या बोले गए शब्दों को पढ़ना या सुनना होगा, और उन्हें सही मानते हुए, यह तय करना होगा कि क्या धारा 196 के तहत कोई अपराध हुआ है - यह तय करने के लिए कि क्या सामग्री संज्ञेय अपराध करने का मामला बनाती है, लिखे हुए शब्दों को पढ़ना, या बोले गए शब्दों को सुनना ज़रूरी होगा - धारा 197, 299 और 302, BNS के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में भी यही बात लागू होती है - इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ऑफिसर को मिली जानकारी से कोई संज्ञेय अपराध बनता है, ऑफिसर को बोले गए या लिखे गए शब्दों का मतलब समझना चाहिए - पुलिस ऑफिसर का यह काम प्रारंभिक जांच करने जैसा नहीं होगा जो धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत अनुमत नहीं है। [पैरा 25,26,28]

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -धारा 154 - एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता - s.173, बी. एन. एस. एस. बनाम धारा 154, सी. आर. पी. सी.-ललिता कुमारी निर्णय पर चर्चा की गई -धारा 173(3) सीआरपीसी की धारा 154 से महत्वपूर्ण विचलन। [पैरा 23, 24, 42]**

**भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023-s। 528- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - एफआईआर को रद्द करना - भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - उच्च न्यायालय ने इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया कि जांच प्रारंभिक चरण में है - क्या यह सही है:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि जब जांच शुरुआती स्टेज में हो, तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 या CrPC की धारा 482 (जो BNSS की धारा 528 के बराबर है) के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी अपराध को रद्द नहीं कर सकता - ऐसा कोई आम नियम नहीं है जो सिर्फ इस आधार पर हाई कोर्ट की एफ आई आर रद्द करने की शक्तियों पर रोक लगाता हो कि जांच शुरुआती स्टेज में थी - जब हाई कोर्ट, दिए गए मामले में, पाता है कि पहली नज़र में कोई अपराध नहीं बनता है, तो कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, वह हमेशा दखल दे सकता है, भले ही जांच शुरुआती स्टेज में हो - यह सब हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। [पैरा 42]

**भारत का संविधान- अनुच्छेद 19- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व-न्यायालयों का कर्तव्य-गणना की गई। [पैरा 38-40, 42 (viii)]**

**भारतीय न्याय संहिता, 2023-एस. 196- लागू होने योग्य मानक:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** जब BNS की धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के असर पर विचार समझदार, मज़बूत इरादों वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर किया जाएगा, न कि कमज़ोर और अस्थिर मन वाले लोगों के मानकों के आधार पर - बोले गए या लिखे गए शब्दों के असर का आकलन ऐसे लोगों के मानकों के आधार पर नहीं किया जा सकता जिन्हें हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है या जो हमेशा आलोचना को अपनी शक्ति या पद के लिए खतरा मानते हैं। [पैरा 33,42]

**दंड संहिता, 1860-एस. 153-ए- भारतीय न्याय संहिता- एस। 196- "मेन्स रिया"- आवश्यक घटक:**

**अभिनिर्धारित किया गया:** धारा 196, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध के लिए मेन्स रिया (दोषपूर्ण मानसिक अवस्था) का होना अनिवार्य है। तथ्यों के आधार पर, बोले गए शब्दों के पाठ तथा जिस संदर्भ में वे बोले गए, उन्हें देखते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की मेन्स रिया का आरोपण करना असंभव है। [पैरा 34]

### उद्धृत न्यायिक दृष्टांत

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, [2013] 14 एससीआर 713 : (2014) 2 एससीसी 1 – अनुसरण किया गया।

नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य [2021] 4 एससीआर 1044 : 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315; मंज़र सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य [2007] 4 एससीआर 907 : (2007) 5 एससीसी 1; रमेश बनाम भारत संघ [1988] 2 एससीआर 1011 : (1988) 1 एससीसी 668; जावेद अहमद हाजम बनाम महाराष्ट्र राज्य [2024] 3 एससीआर 317 : (2024) 4 एससीसी 156; पेट्रीसिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य [2021] 7 एससीआर 65 : (2021) 15 एससीसी 35; हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल [1990] Supp. 3 एससीआर 259 : (1992) Supp. 1 एससीसी 335; श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ [2015] 5 एससीआर 963 : (2015) 5 एससीसी 1 - का संदर्भ दिया गया।

आनंद चिंतामणि दिघे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2001 एससीसी ऑनलाइन बॉम 891; भगवती चरण शुक्ला बनाम प्रांतीय सरकार, C.P.& बरार, 1946 एससीसी ऑनलाइन एमपी 5 - का संदर्भ दिया गया।

#### अधिनियमों की सूची

भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारत का संविधान; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; दंड संहिता, 1860।

#### (सूचक शब्दों की सूची)

धारा 196, 197(1), 299, 302, 57 और 3(5), भारतीय न्याय संहिता, 2023; धारा 173(1); 173(3), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(2); भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता; मौलिक अधिकार; मौलिक कर्तव्य; इमरान प्रतापगढ़ी मामला; राज्यसभा सदस्य; कविता पाठ किया; वीडियो के बैकग्राउंड में बोली गई कविता; एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काना; सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म; यांत्रिक रूप से दर्ज की गई FIR; समुदाय की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना; सांप्रदायिक दुश्मनी; वैमनस्य; दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना की भावनाएँ; सार्वजनिक शांति भंग करना; राष्ट्रीय एकता; कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग; भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528; FIR रद्द करना; जांच प्रारंभिक चरण में; धारा 173 BNSS; धारा 154 CrPC; FIR दर्ज करना अनिवार्य; प्रारंभिक जांच; ललिता कुमारी फैसला; संज्ञेय अपराध; प्रथम दृष्टया मामला; "इरादा"; "मेन्स रिया"।

## मामला सामने आ रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील संख्या 1545 /2025  
2025 के एस. सी. आर. ए. (क्यू) संख्या 551 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च  
न्यायालय के दिनांक 17.01.2025 के निर्णय और आदेश से

## दलों के लिए उपस्थिति

अधिवक्ता अपीलकर्ता के लिए:

कपिल सिब्बल, वैभव श्रीवास्तव, सुश्री सुगंधा आनंद।

अधिवक्ता प्रत्यर्चीगण के लिए:

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, ओजस्व पाठक, सुश्री  
राजेश्वरी शंकर।

## उच्चतम न्यायालय का निर्णय / आदेश

### निर्णय

अभय एस. ओका, जे.

### तथ्यात्मक पहलू

1. 26 जनवरी 2025 को भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण हुए। भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार में से एक संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत है। यह बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। यह मामला दर्शाता है कि हमारे संविधान के अस्तित्व के 75 वर्षों के बाद भी, राज्य की कानून प्रवर्तन मशीनरी या तो इस महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के बारे में अनभिज्ञ है या इस मौलिक अधिकार की परवाह नहीं करती है।
2. इस अपील का मुद्दा एक वीडियो क्लिप की पृष्ठभूमि में पढ़ी गई एक कविता के इर्द-गिर्द घूमता है। अपीलकर्ता द्वारा वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। कविता के पाठ को आक्षेपित निर्णय के पैराग्राफ 13 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो इस प्रकार है:

“ए खून (खून) के प्यासों (प्यासा) बात सुनो

गर हक्क (सत्य) की लड़ाई जुल्म (ज्यादती/अन्याय) सही

हम जुल्म (ज्यादती/अन्याय) से इश्क (प्रेम) निभा देंगे

गर शम-ए-गिरिया (मोमबत्ती का पिघलना जो आंसू जैसा दिखता है)

आतिश (लो) है

हर राह वो शम्मा (प्रकाश) जला देंगे

गर लाश हमारे अपनों की खतरा है तुम्हारी मसनद (throne) का उस रब

(god) की कसम हस्ते हस्ते कितनी लाशें दफना देंगे

ए खून के प्यासों बात सुनो”

3. अपीलकर्ता राज्यसभा का सदस्य है। द्वितीय प्रत्यर्थी वही प्रथम सूचना देने वाला है, जिसके कहने पर जामनगर पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफआईआर') दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (संक्षेप में, 'बीएनएस') की धाराएँ 196, 197(1), 302, 299, 57 तथा 3(5) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है। दूसरे प्रत्यर्थी की शिकायत में, उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2024 को, जामनगर नगर निगम के एक सदस्य अल्ताफ गफ्फार भाई काफी के जन्मदिन के मौके पर, संजरी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उक्त नगर पार्षद ने वर्तमान अपीलकर्ता को समारोह में आमंत्रित किया। इस घटना का एक वीडियो बनाया गया था। अपीलकर्ता ने अपने सत्यापित खाते से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में पृष्ठभूमि में ऊपर पुनः प्रस्तुत कविता का पाठ है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कविता के बोले गए शब्द एक समुदाय के लोगों को दूसरे के खिलाफ बताते हैं और यह एक समुदाय की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को आहत करता है। आरोप है कि गाने के बोल में दूसरे समुदाय के लोगों को समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए उकसाया गया था। आरोप है कि अपीलकर्ता द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो ने राष्ट्रीय स्तर पर दो समुदायों के बीच शत्रुता और एक-दूसरे के प्रति घृणा पैदा की। यह भी आरोप लगाया गया कि इसका राष्ट्रीय एकता पर हानिकारक प्रभाव पड़ा।

#### **उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही**

4. अपीलकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (संक्षेप में, 'BNSS') की धारा 528 के तहत, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ मिलकर एक याचिका दायर की, जिसमें उक्त FIR को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त याचिका पर नोटिस जारी करते समय, माननीय न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को कविता के स्रोत का खुलासा करते हुए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा एक शपथ पत्र दाखिल किया गया था। शपथ पत्र के पैराग्राफ 3 से 5 में उन्होंने इस

प्रकार कहा:

“3. इस माननीय न्यायालय के दिनांक 13.01.2025 के मौखिक आदेश, जो कि R/विशेष आपराधिक आवेदन (क्वैशिंग) सं. 551 / 2025 में पारित हुआ, के अनुपालन में मैं यह निवेदन करता/करती हूँ कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर, जिसमें चैटजीपीटी के माध्यम से देखे गए स्रोत तथा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध मत सम्मिलित हैं, संबंधित कविता का श्रेय फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ अथवा हबीब जालिब को दिया जाता है। लेकिन, क्योंकि इंटरनेट पर राय अलग-अलग हैं, इसलिए मैं पक्के तौर पर यह पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि दोनों में से कौन सा लेखक है। चैटजीपीटी खोज इंजन के परिणामों के स्क्रीनशॉट की एक प्रति इसके साथ संलग्न की जा रही है, जिसे परिशिष्ट-A (ANNEXURE-A) के रूप में अंकित किया गया है।

4. यह आगे कहा गया है कि गीत कविता का एक सादा पाठ, यह प्रेम और अहिंसा का संदेश है।

5. मैं आगे गंभीरता से पुष्टि करता हूँ कि मैं विचाराधीन गीत/कविता का लेखक नहीं हूँ। 6. मैं कहता हूँ कि इस शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक उनकी मूल प्रतियों की सही प्रतियां हैं।

(महत्व दिया गया)

5. इस फैसले और आदेश के ज़रिए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चूंकि जांच अभी शुरूआती स्टेज में है, इसलिए **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य**<sup>1</sup> मामले में इस कोर्ट के फैसले को देखते हुए इसमें दखल नहीं दिया जा सकता।

#### प्रस्तुतियाँ

6. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता का निवेदन यह है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कथित अपराधों के किसी भी तत्व को शिकायत और कविता के सादे पठन पर नहीं बनाया गया है। अपील में यह बताया गया है कि, जैसा कि आमतौर पर होता है, सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर वीडियो पोस्ट करने पर कई प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जिनमें से कुछ पक्ष में और कुछ विरोध में होती हैं। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कविता ने लोगों के बीच सामाजिक वैमनस्य पैदा किया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कविता विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों और जाति या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा नहीं देती है। यह प्रस्तुत

किया गया है कि, अपने सादे पठन पर, यह अधिकारों और सत्य के लिए लड़ने के लिए खुद को बलिदान करने के बारे में है। यह कविता अहिंसा को बढ़ावा देती है और यह उपदेश देती है कि अन्याय को प्रेम से सहना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त कविता के आधार पर एफआईआर दर्ज करना अपीलकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने असंवेदनशीलता दिखाई है। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी कविता द्वारा दिए गए संदेश की सराहना करने का प्रयास नहीं किया है।

7. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने एक उचित रुख अपनाया है और उचित निर्णय लेने के लिए इसे न्यायालय पर छोड़ दिया है। हालांकि, उन्होंने यह दलील दी कि अपीलकर्ता ने शपथ लेकर जो बड़ा दावा किया है कि कविता का लेखक या तो फैज़ अहमद फैज़ या हबीब जालिब हो सकता है, वह पूरी तरह गलत है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि शपथ पर अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए उक्त तर्क का कोई आधार नहीं है। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि एफआईआर दर्ज कराना पुलिस का दायित्व है। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की याचिका खारिज करते समय विधि का पालन किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण के बारे में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई आलोचना सही नहीं है।
8. 7 फरवरी 2025 की ऑफिस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि दूसरे प्रत्यर्थी पर दस्ती सर्विस का शपथ पत्र कर दिया गया है। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

### प्रस्तुत दलीलों तथा कथित शब्दों की समीक्षा

9. उक्त कविता का अंग्रेज़ी अनुवाद इस प्रकार है:

“जो खून के प्यासे हैं, वे सुनें।

अगर हमारे अधिकारों की लड़ाई में अन्याय होता है तो हम उस

अन्याय का सामना प्यार से करेंगे।

अगर मोमबत्ती से गिरने वाली बूंदें आग की लपट जैसी हों (तुलना: अगर हमारे चेहरे से निकलने वाले आंसू आग की लपट जैसे हों)

हम इसका उपयोग सभी रास्तों को रोशन करने के लिए करेंगे।

अगर हमारे अपनों की लाशें तुम्हारे सिंहासन के लिए खतरा हैं, तो हम

भगवान की कसम खाते हैं कि हम अपने प्यारों को खुशी-खुशी दफना देंगे।

जो खून के प्यासे हैं, हमारी बात सुनो।”

10. मूल उर्दू संस्करण और इसके अंग्रेजी अनुवाद को सरलता से पढ़ने पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं:

- a) इस कविता का किसी भी धर्म, समुदाय, क्षेत्र या जाति से कोई लेना-देना नहीं है।
- b) कल्पना की किसी भी सीमा तक नहीं, इसकी विषयवस्तु राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करती है;
- c) यह भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है।
- d) इससे पता चलता है कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते हुए अगर हम न्याय के दायरे में आते हैं, तो हम इसका प्यार से सामना करेंगे। हम अपने आंसुओं का उपयोग सभी रास्तों को रोशन करने के लिए आग की लपटों के रूप में करेंगे।
- e) यह सिंहासन (शासकों) को चेतावनी देता है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे प्रियजनों के शव शासकों के लिए खतरा हैं, तो हम अपने प्रियजनों को खुशी-खुशी दफना देंगे।
- f) यह अहिंसा का उपदेश देता है। इसमें कहा गया है कि अगर हमारे अधिकारों की लड़ाई का सामना अन्याय से किया जाता है, तो हम न्याय का सामना प्यार से करेंगे। यह एक संदेश देता है कि अन्याय का बदला नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि इसका सामना प्यार से किया जाना चाहिए।
- g) कविता अन्याय के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में सिंहासन का जिक्र करती है। सिंहासन का संदर्भ प्रतीकात्मक है। यह एक ऐसी इकाई का संदर्भ है जो अन्याय करने के लिए जिम्मेदार है। यह एक चेतावनी देता है कि अगर हमारे प्रियजनों के शव सिंहासन के लिए खतरा बनते हैं, तो हम खुशी-खुशी अपने प्रियजनों की मौत को स्वीकार कर लेंगे। यह सुझाव देता है कि किसी को अन्याय के खिलाफ लड़ाई में जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए; और
- h) इस प्रकार, कविता हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करती है। इसके विपरीत, यह लोगों को हिंसा का सहारा लेने से रोकने और प्यार के साथ अन्याय का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसमें कहा गया है कि अगर अन्याय के साथ हमारी लड़ाई के परिणामस्वरूप हमारे करीबी और प्रियजनों की मौत हो जाती है, तो हमें उनके शवों को दफनाने में खुशी होगी।

### क्या कोई अपराध सिद्ध होता है?

11. अब, आइए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की ओर ध्यान दें, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद याचिका के साथ संलग्न किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार प्रस्तुत है:

“भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 196, 197 (1) 302, 299, 57, 3 (5) के अनुसार, यह इस तरह से है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उपयोगकर्ता नाम लिंक के साथ इमरान प्रतापगढ़ी शायार Imran नाम का एक सत्यापित X खाता बनाया है। //एक्स. कॉम/शायर इमरान सिंह जिसका बायो इमरान प्रतापगढ़ी का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। सांसद राज्य सभा। राष्ट्रीय अध्यक्ष @INC अल्पसंख्यक सदस्य @INC भारत यश भारती पुरस्कार विजेता खाता धारक ने रूमी पार्क मोरकांडा रोड कलावाड़ नाका, जामनगर शहर, जामनगर जिला, गुजरात राज्य में एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम का 46 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसका शीर्षक है 'जामनगर गुजरात के एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत थी' खून के प्यासो बात सुनो अगर हक की जभंदा जुलमा सा है हम जुलमा से इश्क निभा देंगे हम जुलमा से इश्क निभा डेंग गर सममेगिरिया आतिश है हर राह वो सम्मा जला देंगे गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हस्ते हस्ते कितनी लाशें दफना देंग है खून के प्यासो शब्दों के साथ एक वीडियो अपलोड करना "बात सुनो है खून के प्यासो बात सुन" और धर्म, जाति और समाज के बारे में उत्तेजक भाषा का उपयोग करना। भारत में रहने वाले हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य जातियों की भाषा, विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, ऐसे बयान देना जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक हों, ऐसे बयान देना जो राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाते हों, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से बयान देना, धार्मिक टिप्पणी करना, सदमे में डालने के इरादे से लोगों के बीच वीडियो फैलाना, अपराध करने के लिए दूसरों का हवाला देना।”

महत्व दिया गया)

12. कविता में किसी धर्म, जाति या भाषा का उल्लेख नहीं है। यह किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्तियों को संदर्भित नहीं करता है। कल्पना के किसी भी विस्तार से, क्या यह विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है। हम यह समझने में विफल हैं कि उनमें दिए गए बयान राष्ट्रीय एकता के लिए कैसे हानिकारक हैं और ये बयान राष्ट्रीय

एकता को कैसे प्रभावित करेंगे। सीधे तौर पर पढ़ने पर, यह कविता किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं रखती है।

13. अब, आइए हम जांच करें कि क्या कोई अपराध, जैसा कि आरोप लगाया गया है, आकर्षित किया गया है। BNS की धारा 196 इस प्रकार है:

“196. धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। - (1) जो कोई -

(a) चाहे बोले गए या लिखे गए शब्दों से, या इशारों से या दिखने वाले तरीकों से या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए या किसी और तरह से, धर्म, नस्ल, जन्म की जगह, रहने की जगह, भाषा, जाति या समुदाय या किसी भी दूसरे आधार पर, अलग-अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय गुप या जाति या समुदाय के बीच वैमनस्य या दुश्मनी, नफ़रत या बुरी नीयत की भावना को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने की कोशिश करता है;

(b) ऐसा कोई कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है और जो सार्वजनिक शांति को बाधित करता है या बाधित करने की संभावना रखता है; या

(c) किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन इस इरादे से किया जाता है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, या ऐसी गतिविधि में भाग लेते हैं या आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होने का इरादा रखते हैं या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक, नस्ल, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित होंगे या प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से जो भी भय या भय पैदा करने का कारण बनती है या होने की संभावना है। या ऐसे धार्मिक, जातीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्यों के बीच असुरक्षा की भावना,

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

14. खंड 196 के तहत अपराध तब आकर्षित होता है जब शब्द, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय या किसी अन्य आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देते हैं। अपराध तब आकर्षित होगा जब बोले गए या लिखे गए शब्द, या संकेत या दृश्य प्रतिनिधित्व, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। कविता को सीधे पढ़ने पर हम पाते हैं कि इसका किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या किसी विशेष समूह से कोई लेना-देना नहीं है। कविता के शब्द वैमनस्य या घृणा या दुर्भावना की भावना को नहीं लाते हैं या बढ़ावा नहीं देते हैं। यह केवल शासक द्वारा किए गए अन्याय को चुनौती देना चाहता है। यह कहना असंभव है कि अपीलकर्ता द्वारा उपयोग किए गए शब्द सार्वजनिक शांति को बाधित करते हैं या बाधित करने की संभावना रखते हैं। अतः, धारा 196(1) के खंड (a) अथवा खंड (b) में से कोई भी लागू नहीं होता है। "अपीलकर्ता के खिलाफ किसी भी अभ्यास, आंदोलन, अभ्यास या इसी तरह की गतिविधि के आयोजन का कोई आरोप नहीं है। अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसने किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी भी सभा में ये शब्द कहे थे। अतः खंड (ग) का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। अपीलकर्ता ने एक सामूहिक विवाह समारोह का एक वीडियो लगाया है, और पृष्ठभूमि में, शब्द बोले गए हैं। अतः धारा 196 का कोई अनुप्रयोग नहीं हो सकता है।

15. धारा 197 इस प्रकार है:

"197. राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आरोप, कथन।—(1) जो कोई, बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्यरूपों द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से या अन्यथा,—

(a) ऐसा कोई भी आरोप लगाता या प्रकाशित करता है कि व्यक्तियों का कोई

भी वर्ग, किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण, भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा नहीं रख सकता है, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित या भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखता है; या

(b) यह दावा, परामर्श, सलाह, प्रचार या प्रकाशन करता है कि किसी वर्ग के व्यक्तियों को, किसी धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय का सदस्य होने के कारण, भारत के नागरिक के रूप में उनके अधिकारों से वंचित किया जाएगा या उनसे वंचित किया जाएगा; या

(c) किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के सदस्य होने के कारण किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के दायित्व के बारे में कोई दावा, परामर्श, याचिका या अपील करता है या प्रकाशित करता है और ऐसा दावा, परामर्श, याचिका या अपील ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच सद्भाव या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावना का कारण बनता है या होने की संभावना है; या

(d) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालते हुए गलत या भ्रामक जानकारी देता है या प्रकाशित करता है।

कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी किसी भी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगी किसी सभा में उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

16. जैसा कि पहले कहा गया है, कविता में कोई आरोप नहीं लगाया गया है या प्रकाशित नहीं किया गया है और यह किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय से संबंधित नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को नागरिक के रूप में अधिकारों से वंचित किया गया है क्योंकि वे धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूह, जाति या समुदाय के सदस्य हैं। यह ऐसा कोई दावा, सलाह, गुजारिश या अपील नहीं करता या प्रकाशित नहीं करता जिससे असहमति या दुश्मनी, नफरत या बुरी भावना पैदा हो। यह कविता कोई भी गलत या गुमराह करने वाली जानकारी प्रकाशित नहीं करती है।

17. अपीलकर्ता के खिलाफ बी. एन. एस. की खंड 299 के तहत अपराध का भी आरोप लगाया गया है, जो इस प्रकार है:

“299. जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य अपमान करना है अपने धर्म का अपमान करके किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाएँ या धार्मिक मान्यताएँ.— जो कोई भी, भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के जानबूझकर और बुरे इरादे से, शब्दों से, चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों, या संकेतों से या दिखाई देने वाली चीज़ों से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से या किसी और तरह से, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या अपमान करने की कोशिश करता है, उसे किसी भी तरह की कैद की सज़ा दी जाएगी जो तीन साल तक हो सकती है, या जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों सज़ाएँ दी जाएंगी।”

कम से कम यह कहना हास्यास्पद है कि अपीलकर्ता के कार्य का उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है। कविता केवल शासकों को बताती है कि अगर अधिकारों के लिए लड़ाई को अन्याय का सामना करना पड़ता है तो क्या प्रतिक्रिया होगी।

18. यहां तक कि बी. एन. एस. की धारा 302 के तहत अपराध का भी आरोप लगाया गया है, जो इस प्रकार है:

“302. किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर शब्द, आदि का उच्चारण करना।—जो कोई भी, किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जानबूझकर इरादे से, कोई भी शब्द बोलता है या उस व्यक्ति के सुनने में कोई आवाज करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई इशारा करता है या उस व्यक्ति की दृष्टि में कोई भी वस्तु रखता है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

यदि किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर कोई शब्द बोला जाता है तो धारा 302 के तहत अपराध माना जाएगा। यह धारा अपने स्पष्ट पाठ के अनुसार भी लागू नहीं होती है।

19. बी. एन. एस. की धारा 57 कथित रूप से लागू होती है, जो इस प्रकार है:

“57. आम जनता या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध के लिए

दुष्प्रेरण।—जो कोई भी आम जनता द्वारा या किसी भी संख्या या दस से अधिक व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अपराध करने के लिए उकसाता है, उसे सात साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।"

हम यह समझने में विफल हैं, भले ही यह माना जाता है कि अपीलकर्ता ने कुछ अपराध किया है, उसने आम तौर पर जनता द्वारा या किसी भी संख्या या दस से अधिक व्यक्तियों के वर्ग द्वारा अपराध करने के लिए कैसे उकसाया है।

### प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का दायित्व

20. सवाल यह है कि क्या मामले के तथ्यों के आधार पर, BNSS की धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत FIR दर्ज करना ज़रूरी था। धारा 173, जो संज्ञेय मामलों में जानकारी से संबंधित है, इस प्रकार है:

"173. संज्ञेय मामलों में जानकारी .—(1) किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है, और यदि दी जाती है -

(i) मौखिक रूप से, यह उसके द्वारा या उसके निर्देश के तहत लिखित होगा, और सूचना देने वाले को पढ़ा जाएगा; और ऐसी प्रत्येक जानकारी, चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या लिखित रूप में कम की गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, यह देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसके द्वारा रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और इसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखे जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा जो राज्य सरकार इस संबंध में नियमों द्वारा निर्धारित करे:

बशर्ते कि अगर जानकारी उस महिला द्वारा दी जाती है जिसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के तहत अपराध करने या करने की कोशिश करने का आरोप है, तो ऐसी जानकारी एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी:

आगे कहा गया है कि -

(a) अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के तहत अपराध करने या करने की कोशिश करने का आरोप है, वह अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी जानकारी एक पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के घर पर या उस व्यक्ति की पसंद की किसी सुविधाजनक जगह पर, एक दुभाषिया या एक विशेष शिक्षक की उपस्थिति में दर्ज की जाएगी, जैसा भी मामला हो;

(b) ऐसी जानकारी की रिकॉर्डिंग वीडियो ग्राफ़ की जाएगी।

(c) पुलिस अधिकारी धारा 183 की उप-धारा (6) के खंड (ए) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए **व्यक्ति** का बयान जल्द से जल्द प्राप्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत मुफ्त में दी जाएगी।

(3) धारा 175 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर, जो तीन वर्ष या उससे अधिक लेकिन सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय है, पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए, पुलिस उप अधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर,—

(i) यह पता लगाने के लिए कि क्या चौदह दिनों की अवधि के भीतर मामले में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है, प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़ें; या

(ii) जब कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद हो तो जांच के साथ आगे बढ़ें।

(4) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो, यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां

होंगी, जो ऐसा करने में विफल रहने पर, पीड़ित व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास आवेदन कर सकता है।"

उप-धारा (1) में संज्ञेय अपराध करने से संबंधित जानकारी देने का प्रावधान है। यह मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दिया जा सकता है। यदि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो सूचना के सार को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज करना अनिवार्य है। यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है तो पुलिस अधिकारी द्वारा आगे कोई जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए धारा 173 की उपधारा (3) द्वारा बनाए गए अपवाद के अधीन, जिस पर हम बाद में विचार करेंगे, सूचना को पुस्तक में दर्ज करना अनिवार्य है। इस प्रकार, यदि प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

21. सी. आर. पी. सी. की धारा 154 इस प्रकार है:

"154. संज्ञेय मामलों में जानकारी .-(1) संज्ञेय अपराध होने से संबंधित  
हर जानकारी, अगर किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से दी जाती है, तो वह उसे खुद या अपने निर्देश पर लिखकर दर्ज करेगा, और जानकारी देने वाले को पढ़कर सुनाएगा; और ऐसी हर जानकारी, चाहे लिखित में दी गई हो या जैसा ऊपर बताया गया है, लिखकर दर्ज की गई हो, उस पर जानकारी देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक किताब में ऐसे फॉर्म में दर्ज किया जाएगा जैसा राज्य सरकार इस संबंध में तय करे:

बशर्ते कि अगर जानकारी उस महिला द्वारा दी जाती है जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (45 / 1860) की धारा 326-A, धारा 326-B, धारा 354, धारा 354-A, धारा 354-B, धारा 354-C, धारा 354-D, धारा 376, धारा 376-A, धारा 376-AB, धारा 376-B, धारा 376-C, धारा 376-D, धारा 376-DA, धारा 376-DB, धारा 376-E या धारा 509 के तहत अपराध करने या करने की कोशिश करने का आरोप है, तो ऐसी जानकारी एक महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी:

आगे कहा गया है कि -

(a) यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (45/1860) की धारा

354, धारा 354-ए, धारा 354-बी, धारा 354-सी, धारा 354-डी, धारा 376, धारा 376-ए, धारा 376-एबी, धारा 376-बी, धारा 376-सी, धारा 376-डी, धारा 376-डीए, धारा 376-डीबी, धारा 376-ई या धारा 509 के अंतर्गत अपराध किए जाने या प्रयास किए जाने का आरोप है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, तो ऐसी सूचना एक पुलिस अधिकारी द्वारा, ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने के इच्छुक व्यक्ति के निवास पर या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में, जैसा भी मामला हो, दर्ज की जाएगी;

(b) ऐसी जानकारी की रिकॉर्डिंग वीडियो ग्राफ की जाएगी।

(c) पुलिस अधिकारी यथाशीघ्र, धारा 164 की उप-धारा (5-A) के खंड (a) के अंतर्गत किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन दर्ज करवाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक प्रति सूचना देने वाले को तुरंत मुफ्त में दी जाएगी।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना को दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की ओर से इनकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार, लिखित रूप में और डाक द्वारा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है, जो, यदि संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, तो या तो स्वयं मामले की जांच करेगा या इस संहिता द्वारा प्रदान किए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करने का निर्देश देगा, और ऐसे अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी।"

22. बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (1) काफी हद तक आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'सी. आर. पी. सी.') की धारा 154 की उप-धारा (1) जैसी ही है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार<sup>2</sup> के मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 पर निर्धारित कानून प्रासंगिक होगा। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 120 में निष्कर्ष/निर्देश इस प्रकार हैं:

"120. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं:

120.1 संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है,

यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

120.2. यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं।

120.3 यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां प्रारंभिक जांच शिकायत को बंद करने में समाप्त होती है, इस तरह के समापन की प्रविष्टि की एक प्रति पहले सूचना देने वाले को तुरंत और एक सप्ताह के बाद नहीं दी जानी चाहिए। शिकायत को समाप्त करने तथा आगे कार्यवाही न करने के संक्षिप्त कारणों का प्रकटीकरण अनिवार्य है।

120.4 यदि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया जाता है तो पुलिस अधिकारी अपराध दर्ज करने के अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता है। गलती करने वाले उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो जानकारी मिलने पर भी FIR दर्ज नहीं करते, जबकि मिली जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता हो।

120.5 प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

120.6 किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जानी है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जिन मामलों में प्रारंभिक जांच की जा सकती है, उनकी श्रेणी इस प्रकार है:

- (a) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद
- (b) व्यावसायिक अपराध
- (c) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले
- (d) भ्रष्टाचार के मामले
- (e) जिन मामलों में आपराधिक अभियोजन शुरू करने में असामान्य देरी होती है, उदाहरण के लिए, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना

मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और उन सभी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

**120.7** अभियुक्त और शिकायतकर्ता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए, एक प्रारंभिक जांच समयबद्ध की जानी चाहिए और किसी भी मामले में यह आम तौर पर पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए और असाधारण मामलों में, पर्याप्त कारण बताते हुए, छह सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। इस तरह की देरी का तथ्य और इसके कारण सामान्य डायरी प्रविष्टि में परिलक्षित होने चाहिए।

**120.8** चूंकि जनरल डायरी/स्टेशन डायरी/डेली डायरी पुलिस स्टेशन में मिली सभी जानकारी का रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि संज्ञेय अपराधों से संबंधित सभी जानकारी, चाहे उससे FIR दर्ज हो या जांच हो, उसे अनिवार्य रूप से और विस्तार से उस डायरी में दर्ज किया जाना चाहिए और जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रारंभिक जांच करने का फैसला भी उसमें दर्ज होना चाहिए।

(महत्व दिया गया)

23. सी. आर. पी. सी. की धारा 154 में कोई प्रारंभिक जांच करने का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, जैसा कि **ललिता कुमारी<sup>2</sup>** के मामले में कहा गया है, प्रारंभिक जाँच की अनुमति है यदि प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है और जाँच की आवश्यकता का संकेत देती है। एक प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जानी चाहिए कि क्या एक संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है। हालाँकि, बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) सी. आर. पी. सी. की धारा 154 से महत्वपूर्ण विचलन करती है। इसमें प्रावधान है कि जब किसी संज्ञेय अपराध के करने से संबंधित जानकारी, जिसे 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम के लिए दंडनीय बनाया जाता है, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ प्राप्त की जाती है, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, तो पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है कि क्या कार्यवाही के लिए कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है। हालाँकि, **ललिता कुमारी<sup>2</sup>** के मामले में आईपीसी की धारा 154 के तहत, यह पता लगाने के लिए केवल एक सीमित प्रारंभिक जांच की अनुमति है कि क्या प्राप्त जानकारी एक

संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. के तहत प्रारंभिक जांच तभी की जा सकती है जब जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है। बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) धारा 173 की उप-धारा (1) का अपवाद है। उप-धारा (3) द्वारा कवर किए गए मामलों की श्रेणी में, एक पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनाया गया है, भले ही प्राप्त जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती हो। यह बहुत स्पष्ट है क्योंकि धारा 173 की उप-धारा (3) स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध करने से संबंधित जानकारी प्राप्त करने को संदर्भित करती है। इसलिए, ऐसे मामले में जहां धारा 173 की उपधारा (3) लागू होती है, भले ही किसी संज्ञेय अपराध के होने से संबंधित सूचना प्राप्त हो, यह पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्देश्य तुच्छ मामलों में एफ. आई. आर. के पंजीकरण को रोकना है जहां सजा 7 साल तक है, भले ही जानकारी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती हो। हालाँकि, सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत, ललिता कुमारी<sup>2</sup> के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 120.2 द्वारा अनुमत जांच केवल यह पता लगाने के लिए सीमित है कि क्या संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है।

24. बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत, प्रारंभिक जांच करने के बाद, यदि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए एक प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है, तो उसे तुरंत एक प्राथमिकी आर. दर्ज करनी चाहिए और जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन, यदि उसका विचार है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, तो उसे तुरंत पहले सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को सूचित करना चाहिए ताकि वह धारा 173 की उप-धारा (4) के तहत उपचार का लाभ उठा सके।
25. बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) के मामले के तथ्यों पर लागू होने से पहले, हमें धारा 173 की उप-धारा (1) पर विचार करना चाहिए। एक ऐसा मामला तब जहां एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क करता है और आरोप लगाता है कि उसने 'ए' को छड़ी से 'एक्स' पर हमला करते देखा है। यदि चोट साधारण है तो यह बीएनएस की धारा 115 (2) के तहत दंडनीय अपराध होगा। बी. एन. एस. एस. की पहली अनुसूची के अनुसार, यह एक गैर-संज्ञेय अपराध है। इसलिए ऐसी जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज

नहीं की जा सकती है। यदि गंभीर चोट पहुँचाई जाती है, तो यह बी. एन. एस. की धारा 117 (2) के तहत दंडनीय अपराध होगा, जो एक संज्ञेय अपराध है। इसलिए, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को दी गई जानकारी में लगाए गए आरोपों की जांच केवल एक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है। जानकारी को सही मानते हुए, अधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि क्या यह संज्ञेय अपराध करने का मामला है। यदि आरोप एक संज्ञेय अपराध का मामला बनाता है, जब तक कि अपराध धारा 173 की उप-धारा (3) में नहीं आता है, तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

26. अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पर लौटते हुए, यह निर्धारित किया जाना है कि क्या बोले गए या लिखित शब्दों, अथवा संकेतों, दृश्य प्रस्तुतियों या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अथवा किसी अन्य तरीके से प्रयुक्त शब्द, धारा में निहित परिणामों को जन्म देते हैं या नहीं। जिस पुलिस अधिकारी को जानकारी दी जाती है, उसे लिखे या बोले गए शब्दों को पढ़ना या सुनना होगा, और उन्हें सही के रूप में लेते हुए, यह तय करना होगा कि धारा 196 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। लिखित शब्दों को पढ़ना, या बोले गए शब्दों को सुनना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या सामग्री संज्ञेय अपराध का मामला बनाती है। बी. एन. एस. की धारा 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में भी यही स्थिति है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध है, अधिकारी को बोले गए या लिखित शब्दों के अर्थ पर विचार करना चाहिए। पुलिस अधिकारी की ओर से यह कार्य प्रारंभिक जांच करने के बराबर नहीं होगा जो धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत अनुमेय नहीं है।

27. हम एक उदाहरण देंगे। एक व्यक्ति निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करता है। “अगर शासक मुझ पर हमला करते हैं, तो मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा और इसके विपरीत, हमले का प्यार से सामना करूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो इससे शासकों की हार होगी।” यदि जानकारी देने वाला व्यक्ति यह आरोप लगाता है कि ये शब्द धारा 196 में दिए गए विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए बोले या लिखे गए हैं, तो यह तय करते समय कि क्या जानकारी संज्ञेय अपराध की है, संबंधित अधिकारी को कथित बोले गए शब्दों के अर्थ को पढ़ना और समझना होगा। यह कवायद प्रारंभिक जांच करने के बराबर नहीं है जो बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत निषिद्ध है।

28. बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले अधिकारी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का विवेक प्रदान करती है कि क्या कोई प्रथमदृष्टया मामला आगे बढ़ने के लिए मौजूद है। यह विकल्प तब उपलब्ध होता है जब कथित अपराध को 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम के लिए दंडनीय बनाया जाता है। मामले के तथ्यों में, बी. एन. एस. की धारा 57 के तहत अपराध को छोड़कर सभी अपराध 7 साल से कम के कारावास से दंडनीय हैं। इसके बावजूद, धारा 57 लागू नहीं होती है। इसलिए, यह विकल्प वर्तमान मामले में पुलिस अधिकारी के लिए भी उपलब्ध था। अधिकारी ने उक्त विकल्प का प्रयोग नहीं किया।
29. इस स्तर पर, हम संविधान के अनुच्छेद 51-ए के खंड (ए) का उल्लेख कर सकते हैं, जो इस प्रकार है:

“51-A. मौलिक कर्तव्य.—यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा -

(a) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।

.....”

पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। संविधान का दर्शन और उसके आदर्श प्रस्तावना में ही पाए जा सकते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और अपने सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इसलिए, विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आदर्शों में से एक है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पुलिस तंत्र संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के साथ राज्य से अलग है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी भी नागरिक होने के नाते, संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। वे सभी नागरिकों को प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के लिए एक अपवाद बनाता है। यदि खंड (2) के अंतर्गत आने वाली कोई विधि है, तो उसका संचालन खंड (1) के उपखंड (ए) से अप्रभावित रहता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि खंड (2) द्वारा कवर किए गए कानून एक

अपवाद के रूप में संरक्षित हैं बशर्ते वे एक उचित प्रतिबंध लगाते हैं। अनुच्छेद 19 (2) अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत दी गई स्वतंत्रता का अपवाद है। अनुच्छेद 19(2) में प्रदत्त उचित प्रतिबंध उचित ही रहने चाहिए, काल्पनिक एवं दमनकारी नहीं। अनुच्छेद 19 (2) को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार सहित अनुच्छेद 19 (1) के तहत मूल अधिकारों को कम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः, जब किसी ऐसे अपराध के किए जाने का आरोप हो जो अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित विधि के अंतर्गत आता हो, और यदि धारा 173 की उप-धारा (3) लागू होती हो, तो यह सदैव उपयुक्त होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आगे की कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं, इसका पता लगाने हेतु एक प्रारंभिक जांच की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उप-खंड (ए) के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। इसलिए, ऐसे मामलों में, धारा 173 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट उच्च पुलिस अधिकारी को सामान्यतः पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। अतः, जब संज्ञेय अपराधों के किए जाने का आरोप लगाया जाता है, जिनमें दंड के रूप में सात वर्ष तक का कारावास निर्धारित है, और जो बोले गए या लिखित शब्दों पर आधारित हों, तो धारा 173 की उप-धारा (3) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करना तथा यह निर्धारित करने के लिए एक प्रारंभिक जांच करना कि आगे कार्यवाही करने हेतु कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है या नहीं, सदैव उपयुक्त होगा। यदि ऐसे मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा (3) के तहत विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है जिसने अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है, भले ही अनुच्छेद 19 का खंड (2) आकर्षित न हो। यदि ऐसे मामलों में धारा 173 की उपधारा (3) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो यह बीएनएसएस की धारा 173 की उपधारा (3) को शामिल करने के उद्देश्य को विफल कर देगा और अनुच्छेद 51-ए (ए) के अंतर्गत पुलिस का दायित्व भी विफल कर देगा।

30. धारा 173 की उपधारा (1) के अधीन किसी दायित्व के पालन के समय भी, जहां अपराध का किया जाना बोले गए या लिखे गए शब्दों पर आधारित है, संबंधित पुलिस अधिकारी को अनुच्छेद 19(1)(ए) के अंतर्गत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना होगा, जिसे अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अंतर्गत दिए गए अपवाद के साथ पढ़ा जा सकता है। इसका कारण यह है कि वह संविधान का पालन करने और संविधान के तहत दिए गए आदर्शों का सम्मान करने के लिए बाध्य है। संविधान 75 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस समय तक पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करने और

संविधान के आदर्शों का सम्मान करने के अपने कर्तव्य के बारे में संवेदनशील होना चाहिए था। यदि पुलिस अधिकारी इन दायित्वों से अवगत नहीं हैं, तो राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके शिक्षित और संवेदनशील हों।

31. मामले के तथ्यों को देखते हुए, बीएनएसएस की धारा 173 की उपधारा (3) का सहारा लिए बिना भी, पुलिस अधिकारी को दी गई सूचना बीएनएस की धाराओं 196, 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों को आकर्षित नहीं करती थी।

### लागू किया जाने वाला मानक

32. इस समय, हम बोस और पुराणिक, जे.जे., ने पहले के नागपुर हाई कोर्ट के जज के तौर पर जो लिखा था, उसे कोट करने के लालच से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। पैराग्राफ 67 में **भगवती चरण शुक्ला बनाम प्रांतीय सरकार, सी. पी. और बेरार<sup>3</sup>** के मामले में यह इस प्रकार माना गया है:

67. विवादित लेख को इस दृष्टिकोण से देखने पर हम इस राय पर पहुँचे हैं कि वास्तव में यह राजद्रोही नहीं है, क्योंकि इसका घोषित उद्देश्य मतपेटी के माध्यम से सरकार में परिवर्तन कराना है, न कि लोगों को सरकारी कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना। इसमें भाषा की कुछ अतिशयोक्ति है, और इसमें वही सामान्य भौंडा भावनात्मक अपील है जो लोकलुभावन नेताओं का खास तरीका होता है, साथ ही कवियों की नकल करने की एक अनाड़ी और अप्रभावी कोशिश भी है। लेकिन बस इतना ही। हालांकि, सिर्फ यह पता लगाना काफी नहीं है कि लेखक राजद्रोह का दोषी नहीं है, क्योंकि हम प्रेस (इमरजेंसी पावर्स) एक्ट की धारा 4 से जुड़े हैं, जो धारा 124 A से ज़्यादा व्यापक है। इसलिए हमें आगे यह देखना होगा कि क्या ये शब्द सीधे या परोक्ष रूप से राजद्रोह भड़काने की कोशिश करते हैं, या, अध्यादेश के शब्दों में, क्या उनका मकसद ऐसा असर पैदा करना है या ऐसा असर होने की संभावना है। हम जानबूझकर यह कहते हैं कि क्या ये शब्द देशद्रोह के लिए उकसाने की संभावना रखते हैं, क्योंकि जैसा कि संघीय न्यायालय ने इंगित किया है, धारा 4 में प्रयुक्त शब्दों का सूत्र, जैसा कि अध्यादेश में भी है, ठीक वही सूत्र है जो धारा 124A में प्रयुक्त है; इसलिए उस सूत्र की सीमा तक दोनों बातें समान हैं। एकमात्र अंतर यह है कि प्रेस अधिनियम के अंतर्गत हमें केवल यह नहीं देखना होता कि वास्तव में देशद्रोह है या नहीं, बल्कि यह भी विचार

करना होता है कि क्या शब्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देशद्रोह के लिए उकसाते हैं और क्या वे ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभिप्रेत हैं या उनकी ऐसी संभावना है। हम यह देखने के लिए रुकते हैं कि यहाँ, जैसा कि आपराधिक मामलों में उचित संदेह के मामले में, और जैसा कि हमले के मामले में चोट के डर के मामले में, हमें उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों का उपयोग करना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों का, न ही उन लोगों का जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं। उन मानकों का उपयोग करते हुए हम एक तथ्य के रूप में मानते हैं कि क्राउन द्वारा पकड़े गए और धारा द्वारा आवश्यक प्रभाव इस लेख के कारण होने की संभावना नहीं है, और न ही उपयोग किए गए शब्द, उनकी उचित सेटिंग में देखे जाने पर, उस प्रभाव का कारण बनते हैं। पेपर अंग्रेजी में है। इसका परिसंचरण सीमित है। इसे वे लोग पढ़ते हैं जो अंग्रेजी जानते और समझते हैं। यह एक दल का समाचारपत्र है और इसे मुख्यतः राजनीतिक सोच रखने वाले लोग पढ़ते हैं। वे समकालीन राजनीतिक विचारों और घटनाओं से अवगत हैं। वे भी किसी और की तरह यह समझते हैं कि न तो महामहिम गवर्नर और न ही उनके सलाहकारों ने घूम-घूमकर लोगों को गोली मारी और मारा। वे जानते हैं कि ये कृत्य सैनिकों और पुलिस द्वारा किए गए थे। वे जानते हैं कि निष्पक्ष जांच और न्यायिक जांच की मांग की गई थी। वे जानते हैं कि मांग को अस्वीकार कर दिया गया था और वे जानते हैं कि जहां तक सरकार का संबंध है, पूरी शिकायत वहीं है। इसलिए वे सरकार को श्री जमनादास मेहता और केंद्रीय विधानसभा के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक जिम्मेदारी देने की संभावना नहीं रखते हैं। वे लेखक के रूप में बहुत जागरूक हैं कि अपील संवैधानिक माध्यमों से सरकार के संवैधानिक परिवर्तन के लिए है। हमारी राय में, वे इसकी अन्यथा व्याख्या नहीं कर सकते थे। इसलिए, हमारे निर्णय में, लेख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजद्रोह की ओर नहीं जाता है, और न ही इसके उस परिणाम को उत्पन्न करने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए आवेदनों की अनुमति दी जानी चाहिए और ज़ब्त करने के आदेशों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि प्रत्येक मामले में लागत का भुगतान क्राउन द्वारा किया जाना चाहिए।"

(महत्व दिया गया)

33. बोस और पुराणिक, जे.जे. द्वारा कही गई बात को कम से कम दो मामलों में सहमति के साथ उद्धृत किया गया है। इस तरह का पहला मामला **मंजार सईद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य**<sup>4</sup> के फैसले में है। दूसरा मामला **रमेश बनाम भारत संघ**<sup>5</sup> के मामले में निर्णय है। अंत में, नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में बोस और जे. जे. पूरनिल द्वारा लिए गए विचार को **जावेद अहमद हाजम बनाम महाराष्ट्र राज्य**<sup>6</sup> के मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ फिर से उद्धृत किया गया है। इस कोर्ट ने जावेद **अहमद हाजम**<sup>6</sup> के मामले में, IPC की धारा 153-A के तहत दंडनीय अपराध पर विचार किया था। IPC की धारा 153-A, BNS की धारा 196 के समान है। एकमात्र अंतर यह है कि BNS की धारा 196 के क्लॉज़ (a) में 'या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से' शब्द जोड़े गए हैं, जो IPC की धारा 153-A के क्लॉज़ (a) में नहीं थे। जब BNS की धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव पर विचार कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के मानकों के आधार पर नहीं, बल्कि समझदार, मजबूत इरादों वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। बोले गए या लिखित शब्दों के प्रभाव को उन लोगों के मानकों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है जिनमें हमेशा असुरक्षा की भावना होती है या जो हमेशा आलोचना को अपनी शक्ति या स्थिति के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।

#### मेनस रिया के आवश्यक तत्व

34. **मंजर सईद खान**<sup>4</sup> और **पैट्रिशिया मुखिम बनाम मेघालय राज्य**<sup>7</sup> के मामले में, इस न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 153-ए में मेन्स रिया के घटक को पढ़ा गया है। **जावेद अहमद हाजम**<sup>6</sup> के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 8 से 14, जो उपरोक्त दोनों निर्णयों का विश्लेषण करते हैं, इस प्रकार हैं:

“8. इस न्यायालय ने **मंजर सईद खान** के मामले में, तत्कालीन नागपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विवियन बोस, जे.द्वारा **भगवती चरण शुक्ला बनाम प्रांतीय सरकार** के मामले में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख किया। उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने IPC की धारा 124-A तथा प्रेस (इमरजेंसी पावर्स) अधिनियम, 1931 की धारा 4(1) के अंतर्गत राजद्रोह के अपराध पर विचार किया। मुद्दा यह था कि क्या प्रेस में एक विशेष लेख, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्थापित कानून सरकार के लिए घृणा या अवमानना लाता है। इस न्यायालय ने **रमेश बनाम भारत संघ** मामले में अपने निर्णय में इस दृष्टिकोण को मंजूरी दी है। उक्त मामले में, इस

न्यायालय ने धारा 153-ए. आई. पी. सी. की प्रयोज्यता के मुद्दे पर विचार किया। पैरा 13 में, यह इस प्रकार आयोजित किया गया था:

“13...शब्दों के प्रभाव को उचित, मजबूत दिमाग वाले, दृढ़ और साहसी पुरुषों के मानकों से आंका जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के, न ही उन लोगों के जो हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण से खतरे की गंध लेते हैं।... यह साधारण तर्कसंगत व्यक्ति का मानक है या जैसा कि वे अंग्रेजी कानून में कहते हैं द मैन ऑन द टॉप ऑफ ए क्लैफम ऑम्निबस।”

(महत्व दिया गया)

इसलिए, धारा 153-ए. आई. पी. सी. के संदर्भ में, बोले गए या लिखे गए शब्दों के प्रभाव का न्याय करते समय, न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा निर्धारित मापदंड को लागू करना होगा।

9. हम पैट्रिशिया मुखिम बनाम स्टेट ऑफ मेघालय मामले में इस कोर्ट के एक फैसले का भी उपयोगी संदर्भ दे सकते हैं। उक्त निर्णय के पैरा 8 से 10 को इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“8. सच सामने आने और एक सभ्य समाज होने के लिए सभी तरह की अभिव्यक्ति को आज़ाद रखना बहुत ज़रूरी है।— थॉमस जेफरसन। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है। हालाँकि, अधिकार आत्यन्तिक नहीं है। भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक आदेश, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वाक्य अपराध (Speech crime) आई. पी. सी. की धारा 153-A के अंतर्गत दंडनीय है। धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने और सामंजस्य बनाए रखने में बाधक कार्य करने पर तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना, या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। चूंकि हमें यह निर्णय लेना है कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 153-A और 505(1)(c) के अंतर्गत अपराध का प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं, इसलिए संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करना प्रासंगिक है, जो निम्नलिखित हैं:

\*\*\*

9. सिर्फ जहाँ लिखे या बोले गए शब्दों में सार्वजनिक अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने या सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने की प्रवृत्ति होती है, वहीं ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए कानून को दखल देने की ज़रूरत होती है। गड़बड़ी फैलाने या लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का इरादा IPC की धारा 153-A के तहत अपराध की ज़रूरी शर्त है और प्रॉसिक्यूशन को सफल होने के लिए मेंस रिया का होना साबित करना होगा।

10. IPC की धारा 153-A के तहत अपराध का मुख्य मकसद अलग-अलग वर्गों के लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावना को बढ़ावा देना है। इरादे का अंदाज़ा मुख्य रूप से लिखी हुई चीज़ की भाषा और उन परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए जिनमें उसे लिखा और प्रकाशित किया गया था। धारा 153-ए के दायरे में शिकायत किए गए मामले को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। आरोप को साबित करने के लिए कोई भी जोरदार शब्दों और अलग-अलग अंशों पर भरोसा नहीं कर सकता है और न ही वास्तव में कोई यहां एक वाक्य और वहां एक वाक्य ले सकता है और उन्हें अनुमानित तर्क की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया से जोड़ सकता है।

(मूल और प्रदत्त में जोर दिया गया)

**10.** अब, धारा 153-ए पर वापस आते हैं, धारा 153-ए आईपीसी की उप-धारा (1) का खंड (ए) तब लागू होता है जब बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों या दृश्यमान चित्रणों या अन्यथा द्वारा, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव या दुश्मनी, नफरत या बुरी भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। वैमनस्य, शत्रुता, घृणा या दुर्भावना को बढ़ावा देना धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति, समुदाय या किसी अन्य आधार पर होना चाहिए। धारा 153-ए आईपीसी की उपधारा (1) का खंड (बी) केवल तभी लागू होगा जब कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण हो और जो सार्वजनिक शांति को भंग करता है या भंग होने की संभावना हो।

**11.** अब, अपीलकर्ता द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रयुक्त शब्दों की ओर आते हुए, हम यहाँ यह नोट कर सकते हैं कि पहला बयान यह है कि 5 अगस्त जम्मू और कश्मीर के लिए काला दिन है। 5-8-2019 यह वह दिन है जिस दिन भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को

निरस्त किया गया था और जम्मू और कश्मीर के दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने पोस्ट किया है कि “अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया, हम खुश नहीं हैं”। एक सादे पाठ पर, अपीलकर्ता का इरादा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निराकरण की कार्रवाई की आलोचना करना था। उन्होंने निराकरण के उक्त कार्य पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। उपरोक्त शब्द किसी भी धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय को संदर्भित नहीं करते हैं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निराकृत होना के निर्णय और उस निर्णय के आधार पर उठाए गए आगे के कदमों के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा एक साधारण *विरोध* है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। उक्त गारंटी के तहत, प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निराकरण की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है या, इस मामले में, राज्य का हर फैसला। उसे यह कहने का अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी निर्णय से नाखुश है।

**12. मंजार सईद खान में, इस न्यायालय ने "इरादे" को उक्त अपराध के एक अनिवार्य घटक के रूप में पढ़ा है।** अपीलकर्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए कथित आपत्तिजनक शब्द या भाव, उन्हें सीधे तौर पर पढ़ने पर, अलग-अलग धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच असामंजस्य या दुश्मनी, नफरत या दुर्भावना की भावना को बढ़ावा नहीं दे सकते। अपीलकर्ता के व्हाट्सएप स्टेटस पर दो कांटेदार तारों की एक तस्वीर है, जिसके नीचे लिखा है कि “5 अगस्त – काला दिन – जम्मू और कश्मीर”। यह उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निराकरण पर उनकी प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। यह ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं दिखाता है जो धारा 153-A के तहत मना है। ज़्यादा से ज़्यादा, यह एक विरोध प्रदर्शन है, जो आर्टिकल 19(1)(a) द्वारा गारंटी दी गई उसकी बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हिस्सा है।

**13. भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निराकरण और जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव की कार्रवाई की आलोचना करने का अधिकार है।** निराकरण किए जाने के दिन को “काला दिवस” के रूप में वर्णित करना विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति है। यदि राज्य के कार्यों की प्रत्येक आलोचना या विरोध धारा खंड 153-ए के तहत अपराध के रूप में माना जाता है, तो

लोकतंत्र, जो भारत के संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा।

14. वैध और कानूनी तरीके से असहमति जताने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(a) के तहत गारंटी वाले अधिकारों का एक ज़रूरी हिस्सा है। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के असहमति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। सरकार के फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का अवसर लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वैध तरीके से असहमति के अधिकार को अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत गरिमापूर्ण और सार्थक जीवन जीने के अधिकार के एक हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए। लेकिन विरोध या असहमति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मान्य तरीकों की सीमाओं के अंदर ही होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 19 के खंड (2) के अनुसार लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने सीमा को बिल्कुल भी पार नहीं किया है।"

अतः, BNS की धारा 196 में \*mens rea\* को जोड़ा जाना आवश्यक होगा। इस मामले में, बोले गए शब्दों के पाठ और उस संदर्भ को देखते हुए जिसमें वे बोले गए, अपीलकर्ता पर किसी भी प्रकार का mens rea आरोपित करना असंभव है।

#### आक्षेपित निर्णय

35. अब, हम आक्षेपित निर्णय पर आते हैं। मंजार सईद खान<sup>4</sup> और जावेद अहमद हाजम<sup>6</sup> के मामले में इस अदालत के फैसलों पर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष भरोसा किया। इसलिए, उच्च न्यायालय इस बात से अवगत था कि वह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत अपीलकर्ता के मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा था। उच्च न्यायालय ने फैसले में दोनों फैसलों का विस्तार से हवाला दिया। आश्चर्य की बात यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष। गुण-दोष पर निष्कर्ष केवल निर्णय के पैराग्राफ 22 में है, जो इस प्रकार है:

"22. कविता के भाव को देखते हुए, यह निश्चित रूप से सिंहासन के बारे में कुछ इंगित करता है। उक्त पोस्ट पर अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं से यह भी संकेत मिलता है कि संदेश इस तरह से पोस्ट किया गया था जो निश्चित रूप से सामाजिक सद्भाव में गड़बड़ी पैदा करता है। भारत के किसी भी नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस तरह से व्यवहार करे जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या सामाजिक सद्भाव में खलल न

पड़े और याचिकाकर्ता, जो संसद सदस्य है, से कुछ और अधिक प्रतिबंधित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि उससे इस तरह के पद के परिणामों के बारे में अधिक जानने की अपेक्षा की जाती है।"

36. तत्काल मामले में, जैसा कि हमने देखा है, कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। ऐसे मामले में, प्राथमिकी आर. दर्ज करना एक बहुत ही यांत्रिक अभ्यास प्रतीत होता है और यह कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। वास्तव में, इस तरह की प्राथमिकी आर. का पंजीकरण वस्तुतः विकृति पर निर्भर करता है। हम आश्चर्यचकित हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय के संज्ञान से बच गया। उच्च न्यायालय को इस शरारत को हद तक खत्म कर देना चाहिए था।
37. हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय ने कैसे निष्कर्ष निकाला कि संदेश को इस तरह से पोस्ट किया गया था जो निश्चित रूप से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ देगा। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने एक कारण बताया कि जांच आगे बढ़ने के चरण में थी। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि जब जांच शुरूआती स्टेज में हो, तो हाई कोर्ट भारत के संविधान के आर्टिकल 226 या CrPC की धारा 482 (जो BNSS की धारा 528 के बराबर है) के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किसी अपराध को रद्द नहीं कर सकता। जब हाई कोर्ट, दिए गए मामले में, यह पाता है कि पहली नज़र में कोई अपराध नहीं हुआ है, तो कानून की प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए, वह हमेशा दखल दे सकता है, भले ही जांच शुरूआती स्टेज में हो। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऐसा कोई सर्वव्यापी नियम नहीं है जो केवल इस आधार पर कि जांच प्रारंभिक चरण में थी, उच्च न्यायालय की FIR रद्द करने की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। यदि इस तरह के प्रतिबंध को एक आत्यन्तिक नियम के रूप में लिया जाता है, तो यह उच्च न्यायालय की शक्तियों को काफी हद तक कम कर देगा, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल<sup>8</sup>** के मामले में निर्धारित और मान्यता दी गई है।

### **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व और न्यायालयों का कर्तव्य**

38. व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों द्वारा विचारों और मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति एक स्वस्थ और सभ्य समाज का अविभाज्य हिस्सा है। विचारों और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना, संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सम्मानित जीवन का

नेतृत्व करना असंभव है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, राय या विचारों का विरोध दूसरे दृष्टिकोण को व्यक्त करके किया जाना चाहिए। भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हैं, लेकिन व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए। कविता, नाटक, फिल्म, स्टेज शो, व्यंग्य और कला सहित साहित्य मनुष्य के जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। न्यायालय भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार को बनाए रखने और लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। कभी-कभी, हम, न्यायाधीश, बोले गए या लिखे गए शब्दों को पसंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन, फिर भी, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम न्यायाधीश भी संविधान को बनाए रखने और उसके आदर्शों का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। यदि पुलिस या कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में विफल रहती है, तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें और मूल अधिकार की रक्षा करें। कोई अन्य संस्था नहीं है जो नागरिकों के मूल अधिकार को बरकरार रख सके।

39. न्यायालयों, विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकार की उत्साहपूर्वक रक्षा करने के लिए सबसे आगे होना चाहिए। यह न्यायालयों का परम कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संविधान और संविधान के आदर्शों को कुचला न जाए। अदालतों का प्रयास हमेशा मौलिक अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देना होना चाहिए, जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, जो एक उदार संवैधानिक लोकतंत्र में एक नागरिक को मिलने वाले सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। अदालतों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को विनियमित करने या दबाने के लिए नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में, अदालतों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित संविधान और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
40. इस निर्णय को समाप्त करने से पूर्व, हमें दो महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है। दो दशक से भी अधिक समय पूर्व, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश की जांच की थी, जिसके द्वारा मी नाथूराम गोडसे बोलतोय' नामक नाटक की सभी प्रतियों, पांडुलिपियों आदि को ज़ब्त करने का निर्देश दिया गया था। यह मामला **आनंद चिंतामणि दिघे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**<sup>9</sup> में विचाराधीन था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित ज़बती के आदेश को रद्द करते हुए, पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ (जैसा कि वे

उस समय थे) ने यह टिप्पणी की कि उस विशेष मामले में सरकार ने प्रतीत होता है कि नाटक के विरुद्ध व्यक्त की गई आलोचना और उन लोगों के आक्रोश की भावना के प्रभाव में कार्य किया, जो यह मानते थे कि नाटक ने राष्ट्रपिता की अनुचित आलोचना की है। उन्होंने उन शाश्वत मूल्यों पर प्रकाश डाला जिन पर लोकतंत्र का संविधान आधारित है। एक विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता की स्वीकृति जो मुख्यधारा के अनुरूप नहीं हो सकती है, वे प्रमुख मूल्य हैं। कानून के शासन से विवाहित समाज उन लोगों के अधिकारों को रौंद नहीं सकता है जो ऐसे विचारों का दावा करते हैं जिन्हें अलोकप्रिय या बहुमत द्वारा साझा किए गए विचारों के विपरीत माना जा सकता है। यदि किसी संदेश को चित्रित करने की स्वतंत्रता-चाहे वह कैनवास, गद्य या पद्य में हो- उस संदेश की स्वीकार्यता की लोकप्रिय धारणा पर निर्भर करती है तो नाटककार, कलाकार, लेखक और कवि का अधिकार समाप्त हो जाएगा। लोकप्रिय धारणाएँ स्वतंत्रता की गारंटी जैसे संवैधानिक मूल्यों पर हावी नहीं हो सकती हैं। उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक हिस्सा अनुमोदन के साथ नीचे निकाला गया है:

“19. ....लेकिन, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिन पर लोकतंत्र का संविधान आधारित है। दृष्टिकोण की विविधता के प्रति सहिष्णुता और उन लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वीकृति जिनकी सोच मुख्यधारा के अनुरूप नहीं हो सकती है, वे प्रमुख मूल्य हैं जो सरकार के लोकतांत्रिक रूप की नींव पर हैं। कानून के शासन से विवाहित समाज, उन लोगों के अधिकारों को रौंद नहीं सकता जो ऐसे विचारों का दावा करते हैं जिन्हें अलोकप्रिय या बहुमत द्वारा साझा किए गए विचारों के विपरीत माना जा सकता है। कानून को याचिकाकर्ता के एक नाटककार के तौर पर उन विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान करने के लिए, नाटक में याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करना ज़रूरी नहीं है। दृष्टिकोण की विविधता के प्रति सम्मान और सहिष्णुता ही अंततः एक लोकतांत्रिक समाज और सरकार को बनाए रखती है। अगर किसी संदेश को दिखाने की आज़ादी - चाहे वह कैनवास, गद्य या कविता में हो - उस संदेश की स्वीकार्यता के बारे में लोगों की राय पर निर्भर करती है, तो नाटककार, कलाकार, लेखक और कवि का अधिकार बेकार हो जाएगा। लोकप्रिय धारणाएँ, चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हों, उन मूल्यों पर हावी नहीं हो सकती हैं जिन्हें संविधान हमेशा एक स्वतंत्र समाज बनने के उद्देश्य से स्वतंत्रता की गारंटी के रूप में प्रस्तुत करता है।”

(महत्व दिया गया)

41. **श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघ**<sup>10</sup> के मामले में इस न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A की वैधता की जांच की थी, जो संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने पर दंड का प्रावधान करती थी। उक्त संदर्भ में, पीठ ने अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(2), भारत के संविधान की प्रस्तावना तथा इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया और विस्तृत एवं गहन विश्लेषण के पश्चात यह टिप्पणी की कि लोकतंत्र के संदर्भ में, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलभूत मूल्य है, जिसे हमारे संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत सर्वोपरि महत्व प्राप्त है। यह सबसे बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है।

42. हमारे निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित है:

(i) बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3), सी. आर. पी. सी. की धारा 154 से एक महत्वपूर्ण विचलन करती है। इसके अनुसार, जब किसी पुलिस थाना प्रभारी को किसी ऐसे संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, जो तीन वर्ष या उससे अधिक किंतु सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, तो उसमें उल्लिखित किसी वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति से पुलिस अधिकारी यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार रखता है कि क्या मामले में आगे बढ़ने हेतु कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है या नहीं। हालाँकि, सी. आर. पी. सी. की धारा 154 के तहत, जैसा कि **ललिता कुमारी**<sup>2</sup> के मामले में माना गया है, यह पता लगाने के लिए केवल एक सीमित प्रारंभिक जांच की अनुमति है कि क्या प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। इसके अलावा, सी. आर. पी. सी. के तहत प्रारंभिक जांच तभी की जा सकती है जब जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है। बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3), धारा 173 की उप-धारा (1) के प्रति एक अपवाद है। उप-धारा (3) के अंतर्गत आने वाले मामलों की श्रेणी में, पुलिस अधिकारी को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, भले ही प्राप्त सूचना से किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा हो।

(ii) बी. एन. एस. एस. की धारा 173 की उप-धारा (3) के तहत, प्रारंभिक जांच करने के बाद, यदि अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए एक

प्रथमदृष्टया मामला मौजूद है, तो उसे तुरंत एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जांच के लिए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन, यदि उसका विचार है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है, तो उसे तुरंत पहले सूचना देने वाले/शिकायतकर्ता को सूचित करना चाहिए ताकि वह धारा 173 की उप-धारा (4) के तहत उपचार का लाभ उठा सके।

- (iii) बी. एन. एस. की धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध के मामले में यह तय करने के लिए कि क्या शब्द, या तो बोले गए या लिखित या संकेत द्वारा या दृश्य अभ्यावेदन द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा से या अन्यथा, धारा में प्रदान किए गए परिणामों की ओर ले जाते हैं, जिस पुलिस अधिकारी को जानकारी दी जाती है, उसे लिखित या बोले गए शब्दों को पढ़ना या सुनना होगा, और उसी को सही मानते हुए, यह तय करना होगा कि धारा 196 के तहत अपराध बनाया गया है या नहीं। लिखित शब्दों को पढ़ना, या बोले गए शब्दों को सुनना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या विषय-वस्तु संज्ञेय अपराध का मामला बनाती है। बी. एन. एस. की धारा 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के मामले में भी यही स्थिति है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध है, अधिकारी को बोले गए या लिखित शब्दों के अर्थ पर विचार करना चाहिए। पुलिस अधिकारी की ओर से यह कार्य प्रारंभिक जांच करने के बराबर नहीं होगा जो धारा 173 की उप-धारा (1) के तहत अनुमेय नहीं है।
- (iv) पुलिस अधिकारियों को संविधान का पालन करना चाहिए और उसके आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। संविधान का दर्शन और उसके आदर्श प्रस्तावना में ही पाए जा सकते हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत के लोगों ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और अपने सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इसलिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आदर्शों में से एक है। अनुच्छेद 19 (1) (ए) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पुलिस तंत्र संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य का एक हिस्सा है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी नागरिक होने के नाते संविधान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। वे सभी नागरिकों को प्रदत्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

- (v) संविधान के अनुच्छेद 19 का खंड (2) अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ए) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के लिए एक अपवाद बनाता है। यदि कोई विधि खंड (2) के अंतर्गत आती है, तो उसका प्रवर्तन खंड (1) के उप-खंड (ए) से अप्रभावित रहता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि खंड (2) के अंतर्गत आने वाले कानून, यदि वे युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाते हैं, तो उन्हें अपवाद के रूप में संरक्षण प्राप्त होता है। अतः, जब किसी ऐसे अपराध के किए जाने का आरोप हो जो अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित विधि के अंतर्गत आता हो, और यदि धारा 173 की उप-धारा (3) लागू होती हो, तो अभियुक्त के विरुद्ध आगे कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया मामला बनता है या नहीं, यह निर्धारित करने हेतु प्रारंभिक जांच करना सदैव उपयुक्त होता है। यह सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (ए) के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार सुरक्षित रहें। इसलिए, ऐसे मामलों में, धारा 173 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट उच्च पुलिस अधिकारी को आम तौर पर पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देनी चाहिए।
- (vi) जब बी. एन. एस. की धारा 196 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो बोले गए या लिखे गए शब्दों के असर पर विचार समझदार, मज़बूत इरादों वाले, दृढ़ और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर किया जाएगा, न कि कमज़ोर और अस्थिर मन वाले लोगों के मानकों के आधार पर। बोले गए या लिखित शब्दों के प्रभाव को उन लोगों के मानकों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है जिनमें हमेशा असुरक्षा की भावना होती है या जो हमेशा आलोचना को अपनी शक्ति या स्थिति के लिए खतरे के रूप में देखते हैं।
- (vii) ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि जब जांच प्रारंभिक चरण में हो, तो उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 या CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528 के समकक्ष) के तहत अपराध रद्द करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। जब उच्च न्यायालय किसी मामले में पाता है कि सामने देखकर भी कोई अपराध सिद्ध नहीं होता, और कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक हो, तो वह सदैव हस्तक्षेप कर सकता है, भले ही जांच प्रारंभिक चरण में ही क्यों न हो। यह सब प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल इस आधार पर कि जांच प्रारंभिक अथवा प्रारम्भिक अवस्था में है, उच्च न्यायालय की एफआईआर को रद्द करने की शक्तियों पर कोई पूर्ण अथवा सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

(viii) विचारों एवं मतों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, चाहे वह व्यक्तियों द्वारा हो या व्यक्तियों के समूह द्वारा, एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज का अविभाज्य अंग है। “विचारों एवं मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन जीना असंभव है।” एक स्वस्थ लोकतंत्र में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, राय या विचारों का विरोध दूसरे दृष्टिकोण को व्यक्त करके किया जाना चाहिए। भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को नापसंद करते हैं, लेकिन व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए। कविता, नाटक, फिल्में, मंचीय प्रस्तुतियाँ— जिसमें स्टैंड-अप कॉमेडी, व्यंग्य तथा कला सम्मिलित हैं—मानव जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाती हैं। न्यायालय भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार को बनाए रखने और लागू करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। कभी-कभी, हम, न्यायाधीश, बोले गए या लिखे गए शब्दों को पसंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन, फिर भी, अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम न्यायाधीश संविधान को बनाए रखने और उसके आदर्शों का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। यदि पुलिस या कार्यपालिका संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत गारंटीकृत मूल अधिकार का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने में विफल रहती है, तो अदालतों का कर्तव्य है कि वे हस्तक्षेप करें और मूल अधिकार की रक्षा करें। कोई अन्य संस्था नहीं है जो नागरिकों के मूल अधिकार को बनाए रख सके।

(ix) 75 हमारे गणतंत्र में वर्षों से, हमें अपने मूल सिद्धांतों पर इतना अस्थिर नहीं देखा जा सकता है कि केवल एक कविता का पाठ या उस मामले के लिए, किसी भी प्रकार की कला या मनोरंजन, जैसे कि स्टैंड-अप कॉमेडी, पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा करने का आरोप लगाया जा सकता है। इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से सार्वजनिक क्षेत्र में सभी वैध विचारों को दबाया जा सकता है जो एक स्वतंत्र समाज के लिए बहुत बुनियादी है।

43. “यद्यपि यह निर्णय हम में से एक (न्यायमूर्ति अभय एस. ओका) द्वारा लिखा गया है, तथापि यह न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान सुझावों पर आधारित है।”

44. इन परिस्थितियों में, आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है। हम सिटी ए-डिवीजन पुलिस स्टेशन, जामनगर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 11202008250014/2025 तथा उसके आधार

पर की गई समस्त आगे की कार्यवाहियों को भी रद्द करते हैं। तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है।

मामले का परिणाम: अपील की अनुमति दी गई।

†हेड नोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे

- 
- 1 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315
  - 2 (2014) 2 एससीसी 1
  - 3 1946 एससीसी ऑनलाइन एम पी 5
  - 4 (2007) 5 एससीसी 1
  - 5 (1988)1 एस. सी. सी. 668
  - 6 (2024) 4 एससीसी 156
  - 7 (2021)15 एससीसी 35
  - 8 (1992) सप.1 एस. सी. सी. 335
  - 9 2001 एससीसी ऑनलाइन बीओएम 891
  - 10 (2015) एससीसी 1